

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 3178]** No. 3178] नर्ड दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

का.आ. 3974(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खिनज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) भारत के राजपत्र, (असाधारण) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 2057(अ), तारीख 23 मई 2018, और का. आ 648(अ), तारीख 8 फरवरी 2018 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तिमल नाडू राज्य में एन्नोर- तिरुवल्लूर – बेंगलुरु – पांडिचेरी – नागपट्टिनम – मदुरै – टूटिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा की थी।

और उक्त आधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 26.05.2018 और 16.02.2018 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

4757 GI/2018 (1)

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाश की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी रुकावटों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 (2018 का संख्या 24), की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 15 अगस्त, 2018 जिस तारीख को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम,1993 (1993 का 27) निरसित होगा, एतद्वारा नियत करती है।

## अनुसूची

जिला : तिरुवल्लूर		राज्य : तमिलनाडु									
		<del></del>	<del></del>		क्षेत्रफल	ल					
तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं	उप खण्ड सं.	हेक्टेर	एयर	वर्ग मीटर					
1	2	3	4	5	6	7					
पोन्नेरी	144. वल्लूर	1539		00	06	00					
पोन्नेरी	148. एडयांचावड़ी	81	5	00	06	00					

[फा. सं. एल-14014/7/2018-जी.पी.-॥]

राज किशोर, अवर सचिव

### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2018

S.O. 3974(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.No.2057(E) dated: 23.05.2018 & S.O.No.648(E) dated: 08.02.2018 issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (herein after referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas, a pipeline "Ennore- Tiruvallur -Bengaluru -Pondicherry -Nagapattinam –Madurai- Tuticorin" should be laid in the State of Tamil Nadu by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, copies of the said notifications were made available to the public from 26.05.2018 and 16.02.2018.

And whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report is satisfied that the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the said Land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said Land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & M P Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

#### **SCHEDULE**

District : Tiruvallur		State: Tamil Nadu						
	Name of the Village	Survey No.	Sub Division No.	Area				
Name of the Taluk				Hectare	Are	Square Meter		
1	2	3	4	5	6	7		
Ponneri	144.Vallur	1539		00	06	00		
Ponneri	148.Edayanchavadi	81	5	00	06	00		

•

[F. No. L-14014/7/2018-GP-II] RAJ KISHORE, Under Secy.